विवरण-II

गुजरात को विगत तीन वर्षो अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान आबंटित की गई राशि तथा प्रतिशत उपयोग

कार्यक्रम	1995-1996		1996-1997		1997-98	
	आबंटित की गई राशि (रु. लाख में)	% उपयोग	आबंटित की गई राशि (रु. लाख में)	% उपयोग	आबंटित की गई राशि (रु. लाख में)	% उपयोग
जे.आर.वाई.	14754.11	86.92	6376.25	98.50	7124.30	98.25
ई.ए.एस.*	6970.00	85.52	5850.00	129.42	4320.00	152.97
आई.आर.डी.पी.	3059.22	100.60	3059.22	98.93	3160.43	107.48

* सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटन नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक मांग आधारित योजना है, आंकड़े आबंटन की बजाए केन्द्रीय रिलीज को दर्शाते है ।

Funds for rural employment in West Bengal

864. SHRI .S.RAMACHANDRAN PILLAI: SHRI E. BALANANDAN:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of targets and achievements set out by Government for rural and tribal people of West bengal in Eighth Plan period and for the Ninth Plan period; and

(b) the year-wise allocation of funds by Government for rural employment schemes projects initiated in States during Eighth Plan period?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND-• EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) Jawahar Rozgar Yojana (JRY), Employment Assurance Scheme (EAS), Million Wells Scheme (MWS) and Integrated Rural Development Programme (IRDP) are the major employment schemes being implemented by the Government throughout the country including in the State of West Bengal. No targets are fixed for employment generation for SCs and STs under JRY and EAS as the schemes are self-targetted. However, the mandays generation are monitored separately for SCs and STs. Under MWS, not less than 2/3rd of the funds are to be spent on SCs &STs. Similarly, under IRDP 50% of the beneficiaries are to be selected from SCs and STs. Details of targets and achievements of JRY, EAS, MWS and IRDP programmes during the Eighth Five Year Plan and for the Annual Plan 1997-98 in respect of West Bengal are given in Annexure *[See Appendix 184, Annexure No. 25]*

(b) The year-wise allocation of funds for the major employment schemes such as JRY, MWS and IRDP during 8th plan period is given at Annexure [See Appendix 184, Annexure No. 25(A)] No allocation are made under EAS. However the releases made under EAS are given at Annexure [See Appendix 184, Annexure No. 25(A)]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को हुआ घाटा

865. **श्री ईश दत्त यादव** :
श्री राम गोपाल यादव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को कुल कितना घाटा हुआ है और ऐसी मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के लगातार बढ़ते हुए घाटे को कम करने के लिए कोई ठोस और कारगर कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) एन.टी.सी. के अपने नियंत्रणाधीन 119 मिलें है । वर्ष 1997-98 के लिए एन.टी.सी. का अनतिम कुल निबल घाटा 685.56 करोड़ रुपए है ।

(ख) और (ग) सरकार एन.टी.सी. द्वारा किए गए एकक-वार अर्थक्षमता अध्ययन के आधर पर एन.टी.सी. की अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वागीण सुधार नीति पर विचार कर रही है जिसके लिए वी.आई.